March. 16. 3. 2017
Hindustan Times

The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Punjab Kesari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
Aaj (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Robust data first, a tribunal later

An omnibus mechanism for solving river water disputes may not be a panacea

ourtake

HT 16

The summer of 2016 was ominous for Bangalore. After the Supreme Court directed Karnataka to release 15,000 cusecs of water every day for 10 days to Tamil Nadu, the streets were afire with protests and violence against Tamilians. The crux of the problem: While Karnataka wanted a rejig of the British-era Cauvery water agreement and triple its share, its neighbour argued that it needs more water to sustain its agricultural requirement. Like the Cauvery dispute, several other major inter-state disputes over water have been in the works for more than two decades. In July 2014, the government in the Rajya Sabha listed the number of exiting disputes and their status at the various tribunals that were set up to find a solution: Ravi and Beas Water Tribunal (sub-judice); Cauvery Water Disputes Tribunal (sub judice); Krishna Water Disputes Tribunal II – (sub judice); Vansadhara Water Disputes Tribunal (status: decision awaited) and Mahadayi Water Disputes Tribunal (decision awaited). The bill, water minister Uma Bharti said, proposes to streamline the adjudication of inter-state river water disputes and make the present legal and institutional architecture robust. It proposes to introduce a mechanism to resolve the dispute amicably by negotiations, through a Dispute Resolution Committee to be established by the Centre, consisting of experts, before it is referred to the tribunal.

Many experts have criticised this move, saying that it is nothing but a change of "nameplate" and will not solve the problem. They say this because there is a lack of reliable and transparent data (which can form the basis of an adjudication) and second, states have not been taken into account on the bill. Though the Centre has invoked Article 262 to say that it is well within its rights to do so, no water dispute can be solved without getting the states on board, even if they are BJP-ruled ones. For example, none of the interlinking projects have gathered steam — even though in many cases the states involved are BJP ruled, simply because water is an emotive issue and the local leaders have to take the electorate into account.

There is a severe lack of comprehensive data that looks at hydrology, meteorology, ecology and economy in an integrated fashion. And we must not forget that climate change will have strong impact and our older assumptions will not remain valid and so fresh data is absolutely necessary. Without having that data backbone, it will be difficult for a state-level tribunal or a central body to solve any issue.

3
Covering L., YIS

News item/letter/article/editorial published on March-16-2017 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi) ✓
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

नमामि गंगे के लिए 19 अरब की परियोजनाएं मंजूर

दै- 16-3-17

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

नमामि गंगे अभियान में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति ने 19 अरब रुपये की 20 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें से 13 उत्तराखंड से संबद्ध है। हरिद्वार में मलजल नेटवर्क तैयार करने में करीब 415 करोड़ की लागत आएगी।

जल संसाधन व विकास मंत्रालय ने नमामि गंगे परियोजना के तहत बुधवार को परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं के लिए पूरा खर्च केंद्र सरकार देगी। उसके बाद इनके प्रचालन और रख-रखाव का खर्च भी केंद्र सरकार ही वहन करेगी।

परियोजना के तहत अलकनंदा में प्रदूषण दूर करने के लिए गंदे पानी के नालों को इसमें जाने से रोककर उनका मार्ग बदलना है। इसके साथ ही जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और कीर्तिनगर में नए लघु संयंत्र स्थापित करने हैं जिन पर करीब 78 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गंगा में प्रदूषण दूर करने के लिए ऋषिकेश में 158 करोड़ रुपये की लागत वाली एक बड़ी परियोजना को भी अनुमोदित किया गया है।

News item/letter/article/editorial published on March-16.3.2017 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi) ✓
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

अब गंगा नदी की सफाई होगी और तेज

16-3-17

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली @ पत्रिका. गंगा नदी के प्रदूषण को खत्म करने के लिए केंद्र की सत्तारुढ़ एनडीए सरकार ने सत्ता में आते ही इसके लिए एक महत्वकांक्षी योजना तैयार की थी। केंद्र ने अब इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गंगा को स्वच्छ करने के लिए बीस परियोजनाओं का खाका खींच गया है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति ने इन परियोजनाओं में तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से 19 अरब रुपए की मंजूरी प्रदान की है।

बीस परियोजनाएं स्वीकृत

समिति की ओर से मंजूर की गई बीस परियोजनाओं में से तेरह तो अकेले उत्तराखंड से सम्बद्ध है, जिनमें नए मलजल उपचार संयंत्रों की स्थापना, मौजूदा सीवर उपचार संयंत्रों में सुधार करना शामिल है। हरिद्वार में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। स्वीकृत योजना का लक्ष्य न केवल इस शहर के डेढ़ लाख स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि इस पवित्र स्थान की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उत्सर्जित मलजल का उपचार भी करना है।

अलकनंदा नदी का भी दूर होगा प्रदूषण

उत्तराखंड में अनुमोदित अन्य परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं अलकनंदा नदी का प्रदूषण दूर करने के लिए है, ताकि नीचे की तरफ नदी की धार का स्वच्छ प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। इसमें गंदे पानी के नालों को नदी में जाने से रोकने के लिए उनका मार्ग बदलना, बीच मार्ग में अवरोधक संयंत्र लगाना और साथ ही चार महत्त्वपूर्ण स्थानों जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और कीर्तिनगर में नए छोटे एसटीपीज़ लगाना शामिल है।

शेष अब गंगा @ पेज 13

अब गंगा...

इनके अलावा गंगा का प्रदूषण दूर करने के लिए ऋषिकेश में भी एक बड़ी परियोजना स्वीकृत की गई है। गंगा जैसे ही पर्वत से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसे ऋषिकेश से शहरी प्रदूषक तत्व गंगा में मिलने शुरू हो जाते हैं। गंगा को इन प्रदूषकों से छुटकारा दिलाने के लिए ऋषिकेश में भी एक परियोजना शुरू की जाएगी। इससे न केवल सभी शहरी नालों को ऋषिकेश में गंगा में जाने से